मुख्यमंत्री भजन लाल ने शहरी सेवा शिविर के लिए निर्देश दिये

उन्होंने कहा कि इन शिविरों में नागरिकों से जुड़े प्रकरणों का मौके पर समाधान किया जायेगा

जयपुर, 11 सितम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में आमजन तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शहरी सेवा शिविर का आयोजन करने जा रही है। 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत शहरों को स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाने के साथ ही शिविर में जन समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाएगा।

शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर शहरी सेवा शिविर के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर शहर-कस्बे में इसका व्यापक असर दिखाई दे, इसके लिए अभियान में सभी अधिकारी गंभीरता एवं सेवाभाव के साथ कार्य करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना और उनसे जुड़े प्रकरणों का मौके पर ही समाधान करना है। इसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक विशेष पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिविर के संबंध में विभाग द्वारा समग्र जानकारी की मार्गदर्शिका भी तैयार की जाए।

उल्लेखनीय है कि अभियान के दौरान शहरों में व्यापक स्तर पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को शहरी सेवा शिविर के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर चलने वाले इस अभियान में सभी अधिकारी गंभीरता एवं सेवाभाव के साथ कार्य करें।

नालियों, सीवर लाइन, फेरो कवर और मैनहोल की मरम्मत की जाएगी एवं प्रमुख चौराहों, पार्कों, सामुदायिक केन्द्रों और सार्वजनिक स्थलों का सौन्दर्यीकरण होगा।

शिविर के दौरान विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं के आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति दी जाएगी।

- **शिविर से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि अभियान के दौरान शहरों में व्यापक स्तर पर सफाई व्यवस्था, सुनिश्चित करें तथा नालियों, सीवर लाइन, फेरो कवर व मैन होल की मरम्मत करायें।**

उल्लेखनीय है कि पहले 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविर का आयोजन प्रस्तावित था, लेकिन अब इस अभियान की अवधि में विस्तार किया गया है, जिसके तहत अब यह शिविर15 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। बैठक में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

'खुले बाजार में पदों की नीलामी हो रही है'

हैदराबाद, 11 सितंबर। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (केटीआर) ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार ग्रुप-एक के पदों को बेचकर तेलंगाना के बेरोजगार युवाओं को धोखा दे रही है।

राव ने गुरुवार के अपने बयान में कथित घोटाले के लिए एक न्यायिक जांच और पारदर्शी तरीके से दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। राव ने रिपोर्टों

- **बीआरएस के अध्यक्ष, के.टी. रामाराव ने तेलंगाना सरकार पर नौकरियां बेचने का आरोप लगाया।**

और छात्रों के आरोपों को लेकर चिंता व्यक्ति की, जिनमें कहा गया है कि नौकरियों के लिए भारी मात्रा में धन की मांग की गई थी और दावा किया कि सरकार ने "खुले बाजार में पदों की नीलामी की।"

उन्होंने कहा कि लाखों अभ्यर्थी, जिन्होंने अपने सालों की मेहनत और संसाधन लगाये हैं, को अपनी उम्मीदें कुचली नजर आ रही हैं। उच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए राव ने मांग की कि ग्रुप-एक प्रारंभिक परीक्षा बिना अनियमितता के दोबारा करायी जाये।

सीआरपीएफ का आरोप, सुरक्षा प्रोटोकॉल को नहीं मान रहे राहुल

कांग्रेस ने सीआरपीएफ की रिपोर्ट को राहुल का आंदोलन रोकने की कोशिश करार दिया

नयी दिल्ली, 11 सितंबर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं लेकिन इसकी सूचना नहीं दी जाती है जो सरासर सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस संबंध में सीआरपीएफ की तरफ से पत्र लिखकर कहा गया है कि गांधी सुरक्षा प्रोटोकॉल को नहीं मान रहे हैं और बिना सूचना दिये विदेश यात्रा कर रहे हैं। सुरक्षा बल ने इसे सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताते हुए स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि इससे परेशान होकर यह पत्र लिखना पड़ रहा है।

सीआरपीएफ के वीवीआईपी सुरक्षा प्रमुख सुनील जून ने खड़गे को बुधवार को लिखे पत्र में लिखा है कि गांधी अपनी सुरक्षा को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

गांधी की इस साल की विदेश यात्राओं का विस्तारपूर्वक जिक्र करते हुए जून ने कहा है कि पिछले नौ माह में

- **सीआरपीएफ ने कहा, राहुल विदेश यात्रा की जानकारी भी नहीं देते हैं और भीड़ से मिलते हैं।**
- **कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा यह राहुल को डराने की कोशिश है असल में सरकार राहुल की वोट चोरी विरोधी मुहिम से डर गई है।**

गांधी छह बार विदेश यात्रा कर चुके हैं। पत्र में बताया गया है कि गांधी 30 दिसंबर 2024 से नौ जनवरी 2025 तक इटली की यात्रा पर गये थे। फिर 12 से 17 मार्च तक वियतनाम, 17 से 23 अप्रैल तक दुबई, 11 से 18 जून तक कतर, 25 जून से छह जुलाई तक लंदन और हाल ही में चार दिन के लिए मलेशिया की यात्रा पर गये थे।

सीआरपीएफ द्वारा पत्र को सार्वजनिक करने और इसकी टाइमिंग को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे गांधी को डराने की कोशिश करार दिया है।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने गुरुवार को पत्र का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सीआरपीएफ के पत्र भेजने का समय और उसे तुरंत सार्वजनिक करने की मंशा परेशान करने वाली है। उनका कहना है कि गांधी के सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर लिखे पत्र और उसे सार्वजनिक करने का समय सवाल खड़े करता है।

उन्होंने कहा, """यह पत्र ऐसे समय में आया है जब गांधी चुनाव आयोग की मिलीभगत से भाजपा द्वारा की जा रही वोट चोरी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। क्या यह विपक्ष के नेता को डराने की एक छिपी हुई कोशिश है, जिन्होंने पहले ही एक और खुलासे की घोषणा कर दी है। क्या सरकार उनके द्वारा उजागर किये जाने वाले सच से घबरा गयी है।""

गौरतलब है कि गांधी को ज़ैड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है जो गंभीर खतरे की आशंका वाले व्यक्तियों को प्रदान की जाती है।

ट्रम्प के प्रबल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कुछ सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई और कई घायल हुए और कई गिरफ्तार किए गए। हिंसा और सरकारी संस्थाओं पर हमले की निंदा करने के बजाय ट्रंप ने डेमोक्रेट्स और चुनाव व्यवस्था पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने 2016 में उनका चुनाव "चुरा" लिया, जब जो बाइडन विजेता घोषित किए गए।

विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप ने अमेरिकी राजनीति में एक अलग तरह का वैमनस्य भर दिया। इससे पहले तक वहां राजनीति में विचारों और मुद्दों पर मतभेद होते थे, लेकिन निजी जीवन में राजनीतिक विरोधी भी आपस में दोस्त बने रहते थे। ट्रंप ने अमेरिकी राजनीति की इस परंपरा को बदल डाला।

ट्रंप ने अपनी राष्ट्रपति पद की दौड़ 2015 में शुरू की थी, जिसमें उन्होंने प्रवासियों और मैक्सिकन नागरिकों पर ज़हरीले हमले किए और आरोप लगाया कि ये लोग हिंसा, अपराध और अन्य बुराइयां फैला रहे हैं। लेकिन मुख्यधारा की राजनीति ने इस तरह की बयानबाज़ी पर कोई ध्यान नहीं दिया।

धीरे-धीरे पूरी रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप के आगे झुक गई और उन्हें नफरत और टकराव भरे भाषणों की पूरी छूट दे दी। इसी बीच, अश्वेतों की पुलिस के हाथों मौत पर देशभर में हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। ऐसी घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला पूरे अमेरिका में देखने को मिली। बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद, जो अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, ट्रंप ने अश्वेतों के प्रति नफरत को और हवा दी। उसके बाद से यह लहर और भी तेज़ होती गई।

लेकिन अब आम अमेरिकी नागरिक घटनाओं की इस दिशा को लेकर गहराई से चिंतित हो रहे हैं। लोग अमेरिकी राष्ट्रपति की हरकतों को नकारात्मक रूप से देखने लगे हैं और हाल ही में उनकी लोकप्रियता तेजी से गिर गई है।

चुनाव आयोग पूरे देश में मतदाता सूचियों की विशेष गहन समीक्षा करेगा

चुनाव आयोग ने बताया, यह सारी प्रक्रिया 3-4 माह में पूरी हो जाएगी

नयी दिल्ली, 11 जुलाई। बिहार के बाद अब चुनाव आयोग देश भर में राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की तैयारी कर रहा है और यह काम सभी जगह एक साथ कराने का विचार है।

आयोग के एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा, अब पूरे देश में एसआईआर एक साथ करने का ही विचार बन रहा है। एसआईआर की पूरी प्रक्रिया तीन से चार महीने के बीच सम्पन्न हो जाती है।" आयोग के अधिकारियों के अनुसार, देश भर में एसआईआर शुरू करने के कार्यक्रम को तय किया जाना है।

आयोग सूचियों की समीक्षा शुरू करने के लिए साल में जनवरी, अप्रैल, जुलाई अथवा अथवा अक्टूबर की कोई तिथि चुनता है। इससे लगता है कि इस साल अक्टूबर-नवंबर में कराये जाने

- **चुनाव आयोग ने कहा कि इस प्रक्रिया में बूथ लैवल ऑफिसर की अहम भूमिका है हमारे पास देशभर में 10.5 लाख बीएलओ हैं जिनकी संख्या जल्दी ही 12 लाख की जाएगी।**

वाले बिहार के चुनावों के बाद, आयोग पूरे देश में सभी राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों की सूचियों के एसआईआर के कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है।

एक अधिकारी ने कहा, राज्यों के सीईओ अपने यहां पिछली एसआईआर के बाद बनी मतदाता सूचियों को अपने वेबसाइट पर डालने की तैयारी में हैं। कुछ ने सूची को डाल भी दिया है। ज्यादातर राज्यों में पिछली एसआईआर 2002 से 2004 के बीच कराई गयी थी। दिल्ली में सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण 2008 में हुआ था।

अधिकारियों ने कहा कि पुनरीक्षण के लिए तीन महीने का समय पर्याप्त है और अब डिजिटल प्रौद्योगिकी ने इस काम को और आसान बना दिया है।

उन्होंने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आयोग के अनुसार, इस समय एक बीएलओ को सूची की समीक्षा या विशेष पुनरीक्षण के लिए मतदाताओं को छपा हुआ गणना प्रपत्र पहुंचाने और उसे प्राप्त करने के लिए औसन 950 मतदाताओं (करीब ढ ाई सौ घरों) से सम्पर्क करना होता है। इस समय देश में 10.5 लाख बीएलओ हैं और आयोग इनकी संख्या 12 लाख करने जा रहा है। इससे यह औसत और कम होगा।

भारतीय नागरिक रूसी सेना में शामिल होने के झांसे में नहीं आयें

नयी दिल्ली, 11 सितंबर। रूस की सेना में कुछ भारतीय नागरिकों की भर्ती की मीडिया रिपोर्टों के बीच, विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को आगाह किया है कि वे रूसी सेना में शामिल होने के किसी भी प्रस्ताव के झांसे में न आए, क्योंकि इसमें कई जोखिम हैं।

- **विदेश मंत्रालय ने नागरिकों को इसके खतरों से फिर आगाह किया।**

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती से संबंधित मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि, हमने हाल ही में रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की भर्ती की खबरें देखी हैं। सरकार ने पिछले एक साल में कई मौकों पर इस तरह की कार्रवाई में निहित जोखिमों और खतरों को रेखांकित किया है और तदनुसार भारतीय नागरिकों को आगाह किया है।

उन्होंने कहा कि भारत ने मास्को और यहां, दोनों जगहों पर रूसी अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया है और अनुरोध किया है कि इस प्रथा को समाप्त कर हमारे नागरिकों को वापस भेजा जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कार्यशाला छोड़कर निकल गए। गृह राज्य मंत्री जवाहर बेढ़म उन्हें मनाने भी पहुंचे, लेकिन वे नहीं माने। बाद में डॉ. अग्रवाल ने कहा कि उन्हें भाजपा नेताओं श्रवण बगड़ी और गजेन्द्र सिंह खींवसर से पूर्व निर्धारित मुलाकात के लिए निकलना था। उन्होंने कहा कि "मंत्री बेढ़म ने रुकने का आग्रह किया, लेकिन तय कार्यक्रम के चलते मुझे जाना पड़ा।'

कार्यशाला में मुख्यमंत्री शर्मा, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, केन्द्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, सांसद दामोदर अग्रवाल, वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, प्रदेश महामंत्री जितेन्द्र गोठवाल, पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी सहित अन्य वरिष्ठ नेता मंच पर उपस्थित रहे। कार्यशाला के अंत में युवा मोर्चा अध्यक्ष अंकित चेची द्वारा युवा मैराथन के पोस्टर व टी-शर्ट का विमोचन किया गया। मंच संचालन कुलदीप धनकड़ व मुकेश दाधीच ने किया। सेवा पखवाड़ा अभियान के संयोजक संतोष अहलावत ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी।

केदारनाथ, 2500 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक लाख रुपये खर्च हो चुके थे। डेढ़ सौ रुपये में पानी की बोतल, 2,500 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से जबरन कराए गए पूजा-पाठ, और मंदिर स्टाफ द्वारा चलाए जा रहे आवास घोटालों ने पूरी तस्वीर को और भी गंभीर बना दिया।

ऐसी ही कहानियाँ बैद्यनाथ, हरिद्वार और द्वारका जैसे अन्य पवित्र स्थलों से भी सामने आ रही हैं, जहां दलाल, बिकाऊ कतारें और जर्जर बुनियादी ढांचा श्रद्धालुओं की आस्था की अग्निपरीक्षा ले रहे हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि कैसे भारत के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों की गरिमा छीनी जा रही है... और क्यों वैश्विक मानकों पर आधारित एक "टैंपल चार्टर" ही इसका स्थायी समाधान हो सकता है।

एसआई भर्ती ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अप्रमाणित मान लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट राफेल केस में तय कर चुका है कि दस्तावेज किसी भी माध्यम से मिला हो, यदि वह सही है तो कोर्ट उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। वहीं, यदि दागियों को ट्रेनिंग दी जाएगी तो इससे आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास कम होगा। दूसरी ओर खंडपीठ के अपीलार्थी अमर सिंह व विक्रम पंवार की ओर से मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट पेश की गई है।

ब्लूटूथ से नकल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़ को गिरफ्तार किया गया है।

सिंह ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की ओर से कनिष्ठ न्यायिक, सहायक लिपिक ग्रेड-द्वितीय एवं लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पदों पर सीधी भर्ती के संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2022 12 मार्च 2023 एवं 19 मार्च 2023 को 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की गई थी, जिसमें आरोपी राम प्रकाश जाट का परीक्षा केन्द्र विजयन डी. सूरी जैन विद्यापीठ सी. सै. स्कूल, नागौर (राजस्थान) था और आरोपी सुनील विश्नोई का परीक्षा केन्द्र श्री नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन सी. सै. स्कूल हनुमानगढ़ (राजस्थान) था। संगठित नकल गिरोह के मुख्य आरोपी पौरव कालेर निवासी छापर जिला चूरू द्वारा सालासर से मोबाइल फोन के माध्यम से राम प्रकाश जाट और सुनील विश्नोई को ब्ल्यूटूथ डिवाइस से नकल करवाई थी। इसके लिए 4 लाख रूपये में सौदा तय हुआ था। आरोपी राम प्रकाश जाट नकल कर पास हो गया था और वर्तमान में पॉक्सो कोर्ट कम संख्या - 01 उदयपुर में पदस्थापित था तथा विगत 7 माह से फरार चल रहा था। सुनील विश्नोई जिला सैशन कोर्ट हनुमानगढ़ में पदस्थापित था तथा गिरफ्तारी के भय से गत 6 माह से स्वैच्छिक रूप से अनुपस्थित था एवं फरार चल रहा था।

तीन हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश

नयी दिल्ली, 11 सितंबर। उच्चतम न्यायालय कोलीजियम ने उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों को पदोन्नत कर मुख्य न्यायाधीश बनाने की गुरुवार को सिफारिश की। शीर्ष अदालत

- **न्यायमूर्ति सौमेन सेन को मेघालय, एम. सुंदर को मणिपुर तथा बजंथरी को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जायेगा।**

की ओर से जारी बयान के मुताबिक, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमेन सेन को मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गयी है। इसी प्रकार मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम. सुंदर को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. बी. बजंथरी को उसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गयी है।

मॉरीशस के प्र.मंत्री ने क्रूज से गंगा आरती देखी

वाराणसी, 11 सितंबर। मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम ने गुरुवार शाम वाराणसी में विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के दर्शन किये।

मॉरीशस के प्रधानमंत्री और प्रतिनिधि मंडल आज शाम होटल ताज से रविदास घाट पहुंचा, जहां संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने उनका स्वागत किया। विवेकानंद क्रूज से सभी लोग दशाश्वमेध घाट के लिए रवाना हुए। उन्होंने गंगा आरती का दर्शन-पूजन किया। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। क्रूज के निदेशक विकास मालवीय ने बताया कि आरती के बाद सभी को बनारसी चाट में आलू की टिक्की, गोलगप्पे, पालक चाट, बनारसी लस्सी और कुल्फी खिलायी गयी। बनारसी चाट

- **क्रूज पर उनके लिए बनारस के विशेष व्यंजनों की व्यवस्था भी की गई थी।**

सभी लोगों को खूब पसंद आया। आरती आयोजक अध्यक्ष (गंगा सेवा निधि) सुशांत मिश्र ने बताया कि मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम का आगमन काशी में हुआ है। दशाश्वमेध घाट पर नित्य होने वाली गंगा आरती को उन्होंने देखा। गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, इसलिए गंगा आरती कई दिनों से छत पर ही की जा रही है। कार्यालय के ऊपर छत पर आरती स्थल को फूलों और लाइटों से भव्य तरीके से सजाया गया था।

मोदी के जन्मदिन से गांधी जयंती तक भाजपा का सेवा पखवाड़ा

नयी दिल्ली, 11 सितंबर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती दो अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनायेगी।

इस अभियान में सेवा, स्वच्छता, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रिनर्माण को केन्द्र में रखा गया है। इसके अंतर्गत रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच कैम्प, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण के लिए "एक पेड़ मां के नाम" अभियान, प्रदर्शनी, संवाद कार्यक्रम, दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण, "मोदी विकास

- **सेवा पखवाड़े में मोदी के जीवन व उपलब्धियों पर प्रदर्शनियां लगाई जायेंगी।**

मैराथन", खेल महोत्सव और ड्रॉइंग प्रतियोगिताएँ आयोजित होंगी। भाजपा मुख्यालय में गुरुवार को केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेन्द्र यादव, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन एवं उपलब्धियों पर प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी तथा समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद और सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत समाज के विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करने के साथ-साथ 771 संवाद कार्यक्रम भी देशभर के सभी प्रांतों में आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का 17 सितंबर को जन्मदिवस है और उन्होंने भारत की राजनीति में सेवा, स्वच्छता जैसे मौलिक विषयों को सबके सामने स्थापित किया है।

'मोदी कार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

1500 सीसी डीजल) पर कर घटाकर, 18 प्रतिशत (पहले 29-31प्रतिशत) कर दिया है, जबकि बड़ी कारों (4 मीटर से अधिक, 1500 सीसी से ऊपर की इंजन क्षमता और 170 मिमी से अधिक ग्राउंड क्लीयरेंस) पर कर घटाकर, 40 प्रतिशत (पहले 50 प्रतिशत) किया गया है। इसके साथ ही, केन्द्र सरकार ने मुआवजा उपकर (कैम्पन्सैशन सैस) भी हटा लिया है। पूर्व पत्रकार और मीडिया प्रोफेसर प्रदीप माथुर ने टिप्पणी की, "ऐसी कवायद को आमतौर पर अनैतिक श्रेणी में रखा जाता, लेकिन वर्तमान सरकार इसे अपने विशेषाधिकार के रूप में देखती है।"

मोदी के लेख ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रमुख मोहन भागवत के 75वें जन्मदिन पर उनके लिए लिखा गया "हद से ज़्यादा स्तुतिपरक लेख" संघ नेतृत्व को रिझाने की "हताशा भरी कोशिश" है।

प्रधानमंत्री मोदी ने भागवत की बौद्धिक गहराई और परोपकार से भरे नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि 2009 से आरएसएस प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल संगठन की 100 साल की यात्रा का सबसे परिवर्तनकारी दौर माना जाएगा।

गुरुवार (11 सितंबर 2025) को कई अखबारों में प्रकाशित एक प्रशंसात्मक लेख में, मोदी ने कहा कि भागवत 'वसुधैव कुटुंबकम' के जीवंत उदाहरण हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक परिवर्तन और सद्भाव व भाईचारे की भावना को सशक्त करने के लिए समर्पित किया है।

कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, "प्रधानमंत्री ने आरएसएस नेतृत्व की कृपा पाने की व्यग्रता में मोहन भागवत के 75 वें जन्मदिन पर हद से ज़्यादा स्तुतिपरक लेख लिखा है।"

रमेश ने कहा, "प्रधानमंत्री ने यह याद दिलाया है कि 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपना अमर भाषण दिया था। उन्होंने यह भी याद दिलाया है कि 11 सितंबर 2001 को ही अमेरिका में अल कायदा के आतंकवादी हमले हुए थे।"

कांग्रेस नेता ने 'एक्स' पर आगे लिखा, "लेकिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्रधानमंत्री ने यह उल्लेख नहीं किया कि महात्मा गांधी ने 11 सितंबर 1906 को जोहान्सबर्ग में पहली बार सत्याग्रह का आ ान किया था। उसी दिन दुनिया ने पहली बार इस क्रांतिकारी विचार को सुना था।"

रमेश ने कहा, "बेशक, यह उम्मीद करना बहुत ज़्यादा होगा कि प्रधानमंत्री सत्याग्रह की उत्पत्ति को याद रखें, क्योंकि उनके लिए तो सत्य शब्द ही पराया है।"

उन्होने कहा, "प्रधानमंत्री, जो खुद को "नॉन बायोलॉजिकल" बताते हैं, अपने प्रवचनों को ऐसे प्रस्तुत करते हैं, जैसे वे ईश्वरीय कथन हों।"

राष्ट्रपति व राज्यपाल की विधेयक मंजूरी की समय सीमा पर फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के संदर्भ पर 10 दिन संबंधित पक्षों की दलीलें सुनीं

नयी दिल्ली, 11 सितंबर। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंज़ूरी देने की समय-सीमा निर्धारित करने के विवाद से जुड़े राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुनवाई पूरी होने के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर की संविधान पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें 10 दिनों तक सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

राष्ट्रपति संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 200/201 के तहत, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंज़ूरी देने की समय-सीमा से संबंधित प्रश्न उठाए गए थे।

राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए यह संदर्भ प्रस्तुत किया गया था, जो सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख को किसी भी कानूनी प्रश्न या सार्वजनिक महत्व के तथ्य पर उच्चतम न्यायालय की राय लेने की अनुमति देता है।

राष्ट्रपति ने इस संदर्भ में 14 प्रश्नों पर शीर्ष अदालत की राय मांगी। सवालों में यह भी शामिल है कि क्या देश के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायोचित है। संदर्भ में राय मांगी गई है, "क्या संविधान के अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राज्यपाल और राष्ट्रपति के

- **राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को भेजे रैफरेन्स में शीर्ष न्यायालय से 14 प्रश्नों पर राय मांगी थी।**

निर्णय, कानून के लागू होने से पहले के चरण में न्यायोचित हैं? क्या न्यायालयों के लिए किसी विधेयक के कानून बनने से पहले, किसी भी रूप में, उसकी विषय-वस्तु पर न्यायिक निर्णय लेना अनुमन्य है?"

राष्ट्रपति की ओर से यह भी राय मांगी गयी है कि क्या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल की स्वीकृति के बिना भी लागू कानून है।

इसमें यह भी राय देने को कहा गया है, "क्या संविधान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत वाद के माध्यम से छोड़कर, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए शीर्ष न्यायालय के किसी अन्य अधिकार क्षेत्र को रोकता है?" राष्ट्रपति ने महसूस किया कि मौजूदा परिस्थितियों में जब राज्य सरकारें अक्सर संविधान के अनुच्छेद 32 और 131 का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाती हैं, कानूनी प्रश्नों पर शीर्ष अदालत की राय लेना समय की मांग है।

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति संदर्भ के मामले में 22 जुलाई को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर इन सवालों पर अपना पक्ष रखने को कहा था। शीर्ष अदालत ने 29 जुलाई को कहा था कि वह 29 अगस्त से 10 सितंबर के दौरान सुनवाई संबंधित पक्षों की दलीलें सुनेगी।

गौरतलब है कि न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ (शीर्ष अदालत में) ने आठ अप्रैल, 2025 के अपने एक फैसले में तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि द्वारा 10 विधेयकों को पुन: अधिनियमित किए जाने के बाद राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने के फैसले को अवैध घोषित किया था।

छत्तीसगढ़ में एक करोड़ का इनामी नक्सली ढेर

गरियाबंद, 11 सितंबर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान को गुरुवार को तब बड़ी सफलता मिली, जब सुरक्षा बलों ने एक करोड़ के इनामी नक्सली समेत दस नक्सलियों को मार गिराया।

आज सुबह थाना मैनपुर क्षेत्र के जंगलों में नक्सलियों की सक्रियता की सूचना मिलने के बाद ई 30, विशेष सुरक्षा बल और कोबरा की संयुक्त टीम घटनास्थल की ओर रवाना हुई। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच लंबी और तीव्र मुठभेड़ हुई। जिले के पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि मुठभेड़ में माओवादी केन्द्रीय कमेटी के कई बड़े नक्सली मारे गए हैं। माना जा रहा है कि इनमें एक प्रमुख नक्सली मनोज भी शामिल हैं, जिस पर एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित था। राखेचा ने बताया कि अभियान पूरी तरह से सुरक्षा बलों की रणनीति के तहत संपन्न हुआ।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908